P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4* (Part-1) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

क्षेत्रीय असमानता : भारत में आर्थिक और भौगोलिक प्रभाव

आर. के. मारावी
सहायक प्राध्यापक,
अर्थ शास्त्र विभाग,
विश्वविद्यालय का नाम,
पुष्पराजगढ़, राजेन्दग्राम

सारांश

वर्तमान में असमानता ही देश में सबसे बड़ी समस्या है. हमें इसे ख़त्म करना होगा. सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता और औद्योगिक असमानता ही देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत और नैतिकता ख़त्म होता जा रहा है. व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को जाति और धर्म में बांटा जा रहा है, आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों और अरबपतियों की संख्याँ तो बढ़ रही है, परन्तु समाज के गरीब लोग या तो जिस हाल में थे आज भी वही यथा स्थिति बनी हुई है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय का नींव है. आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय का कल्पना भी नहीं कर सकते. यदि वास्तव में हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो हमें आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना ही होगा.निजीकरण–उदारीकरण–वैश्वीकरण के दौर में हर तरह की असमानता बढ़ी है। अमीरों–गरीबों के बीच, उद्योग–कृषि के बीच, शहर–देहात के बीच असमानता बढ़ी है। इसी तरह क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी है।

मुख्य शब्द : क्षेत्रीय असमानता, समस्यातएं आर्थिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव।

प्रस्तावना

यह आम जानकारी की बात है कि निजीकरण–उदारीकरण–वैश्वीकरण के दौर में हर तरह की असमानता बढ़ी है। अमीरों–गरीबों के बीच, उद्योग–कृषि के बीच, शहर–देहात के बीच असमानता बढ़ी है। इसी तरह क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी है।

बढ़ती क्षेत्रीय असमानता का एक आंकड़ा इस प्रकार है–

1960–61 में दिल्ली का प्रति व्यक्ति उत्पाद 668 रुपये था जबकि बिहार का 215 रुपया। 1990–91 में यह आंकड़ा क्रमशः 11057 और 2660 रुपया हो गया। 2014–15 में यह फिर क्रमशः 252011 रुपया तथा 34850 रुपया हो गया। अनुपात के तौर पर देखें तो दिल्ली और बिहार के प्रति व्यक्ति उत्पाद में 1960–61 में अनुपात करीब तीन गुना तक था जो 1990–91 में करीब चार गुने का हो गया। पर उसके बाद के पच्चीस वर्षों में यह तेजी से बढ़कर करीब आठ गुने का हो गया।

दिल्ली देश की राजधानी है जबकि बिहार देश का एक सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश। इनके बीच बढ़ती असमानता यह भी दिखाती है कि राजधानी और दूर–दराज के प्रदेश किस तरह से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।

यह कहा जा सकता है कि राजधानी में ज्यादा धनी लोगों तथा कंपनियों के मुख्यालयों के संकेन्द्रण की वजह से वहां प्रति व्यक्ति उत्पाद ज्यादा हो सकता है। पर यदि अन्य ज्यादा आगे बढ़े हुए प्रदेशों महाराष्ट्र से तुलना करें तो भी यह असमानता बढ़ती नजर आयेगी। हां, यह जरूर है कि स्वयं महाराष्ट्र के भीतर देश के सबसे गरीब इलाकों में से कुछ मिल जायेंगे मसलन विदर्भ का इलाका।

ठीक उदारीकरण के दौर में इस क्षेत्रीय असमानता के बढ़ने के निश्चित कारण हैं। उदारीकरण की नीतियां लागू होने के साथ न केवल सरकारों ने उद्योग–धन्धों से अपने हाथ खींचे बल्कि प्रदेश सरकारों ने अपने–अपने यहां देशी–विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता करनी शुरू की। इसके लिए पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा छूटें–रियायतें व प्रोत्साहन की घोषणाएं की गईं। देशी–विदेशी पूंजी उधर की ओर ही आकर्षित हुई जहां यह सबसे ज्यादा था। अब सबसे ज्यादा छूटें वे ही प्रदेश दे सकते थे, जो पहले से बेहतर स्थिति में थे यानी आय ज्यादा थी जो पहले से ज्यादा औद्योगीकृत थे। इस तरह वह दुष्चक्र शुरू हुआ जो पहले से आगे बढ़े हुए प्रदेशों को और आगे ले गया। पीछे छूटते प्रदेश और पीछे छूटते चले गये।

पूंजी को आकर्षित करने की इस होड़ ने पूंजीपतियों को और ज्यादा लूट का मौका दिया है और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया है। अक्सर ही पूंजीपति इन रियायतों–प्रोत्साहनों का फायदा उठाकर नयी जगह फिर इसी तरह की रियायत–प्रोत्साहन का फायदा उठाने चल देते हैं।

इस प्रवृत्ति में मजदूर वर्ग की सौदेबाजी की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। फैक्टरी के स्थानांतरण के भय से मजदूर वैसे ही दबाव में रहते हैं ऊपर से प्रदेश सरकारें भी हर तरह से मजदूरों के संगठन और संघर्ष को बाधित करती हैं। ऐसा वे प्रदेश के औद्योगीकरण और पूंजीपतियों को पलायन करने से रोकने के नाम पर करती हैं।

मजदूर वर्ग की इस गिरती हालत के इतर स्वयं पूंजीपति वर्ग के भीतर भी इस बढ़ती असमानता ने आपसी रगड़ को जन्म दिया है। विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्रीय पूंजीपति अपने प्रदेश के पिछड़ते जाने से असंतुष्ट हैं। वे अपने प्रदेश के लिए केन्द्र से ज्यादा सहायता की मांग करते हैं। ठीक इसके उलट आगे बढ़े हुए प्रदेशों के पूंजीपति दूसरे तरह की मांग करते हैं। इसी के नतीजे के तौर पर अभी तमिलनाडु की विधानसभा ने माल और सेवा कर विधेयक (जीएसटी बिल) को अनुमोदित नहीं किया।

एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति की बात करने वाले संघ परिवार के स्वयं सेवक जब दिल्ली में सत्तानशीन हुए तो उन्होंने सहकारी संघवाद (को–ओपरेटिव फेडरलिज्म) की बात की। जुमले उछालने में उस्ताद इन संघियों ने यह कभी स्पष्ट नहीं किया कि इस जुमले का क्या आशय है, और इसके तहत क्या किया जायेगा।

वैसे उदारीकरण की धुर समर्थक इस केन्द्रीयतावादी सरकार को इसकी चिन्ता भी नहीं है। चिन्ता तो उन्हें होनी चाहिए जो पिछड़ रहे हैं। पर पूंजीपति वर्ग का हिस्सा होने के चलते वे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा वे यही कर सकते हैं कि बेहतर सौदेबाजी के लिए कोई नया रास्ता ढूंढे। वैसे अब इन रास्तों की गुंजाइश भी बहुत कम रह गई है।

असमानता ही देश में सबसे बड़ी समस्या है

वर्त्तमान में असमानता ही देश में सबसे बड़ी समस्या है. हमें इसे ख़त्म करना होगा. सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता और औद्योगिक असमानता ही देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है.

सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत और नैतिकता ख़त्म होता जा रहा है. व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को जाति और धर्म में बाँटना जायज नहीं.

आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों और अरबपतियों की संख्याँ तो बढ़ रही है परन्तु समाज के गरीब लोग या तो जिस हाल में थे आज भी वही पे खड़े हैं या नहीं तो और गरीब ही होते जा रहे हैं. आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय का नींव है. आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय का कल्पना भी नहीं कर सकते. यदि वास्तव में हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो हमें आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना ही होगा.

शैक्षिक असमानता के कारण ही हम समाज में वंचित वर्गों को अच्छी शिक्षा दे पाने में असफल साबित हो रहे हैं. हम जानते हैं कि शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता. शिक्षा ऐसी हो जो हमें सोचना सिखाये, कर्त्तव्य और अधिकार का बोध कराये, हमें हमारा हक़ दिलाये और हमें समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाये. क्या हम ऐसी शिक्षा समाज के सभी वर्गों को दे पाने में सफल साबित हो रहे हैं?

क्षेत्रीय असमानता के कारण ही आज हम देश के सभी भागों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं. भारत को विकसित देशों के श्रेणी में लाने के लिए हमें सुदूरवर्ती गाँवों में विकास के किरणों को पहुँचाना होगा. आखिर हम दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के अनुपात में ही अन्य शहरों और गाँवों का विकास करने में असफल क्यों साबित हो रहे हैं? हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा. यदि हम इन्ही शहरों जैसे और शहर बनाने में कामयाब होते हैं तो न सिर्फ इन शहरों पर से लोगों का दवाब कम करने में कामयाब होंगे बल्कि हमें इस तरह के और कई अन्य शहर भी विकसित करने में सफलता मिलेगी जो क्षेत्रीय असफलता को ख़त्म करने में मील का पत्थर साबित होगा।

औद्योगिक असमानता के कारण ही आज हमें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पर रहा है. ऐसा देखा जा रहा है कि जिस शहर में पहले से ही बहुत सारे उद्योग–धंधे लगे हुए हैं आज भी उन्ही जगहों पर नए–नए उद्योग और कल–कारखाने लगते जा रहे हैं. हमें नए–नए औद्योगिक शहर बसाने की जरुरत है. इसके दो फायदे होंगे. एक तो पुराने औद्योगिक शहरों पर जो लोगों का बोझ बढ़ता जा रहा है वह कम होगा और दूसरा हम नए औद्योगिक शहर बसाने में भी कामयाब होंगे.

इसी तरह बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रेल और कृषि आदि अनेक क्षेत्रों में असमानताओं से आम जनों को जूझना पर रहा है. कहीं चौबीसों घंटे बिजली तो कहीं आज भी लोग लालटेन और ढिबरी युग में जीने को विवश हैं. कहीं पानी ही पानी तो कहीं पानी के लिए हाहाकार. कहीं पक्की सड़कों की भरमार तो कहीं कच्ची सड़क भी नहीं. कहीं बड़े–बड़े अस्पताल तो कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं. कहीं रेलवे लाइनों की जाल तो कहीं रेलवे का घोर अभाव. कहीं किसानों के लिए आधुनिक संसाधनों की भरमार तो कहीं किसान बेहाल. यह असमानता उस घुन की तरह है जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला बनाता जा रहा है. हमें हर हाल में इस असमानता को मिटाना ही होगा ।

अध्ययन का उदद्देश्य

प्रस्तुति शोध अध्ययन का मुख्य उदद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं का आर्थिक एवं भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन करना है।

अध्ययन का विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक और द्वतियक समकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्राथमिक और द्वतियक समकों का एकत्रीकरण संबंधित कार्यालयों से कर उनका विश्लेषण और प्रस्तुतीकरण करने का प्रयास किया गया है ।

समस्याएं एवं प्रभाव

क्षेत्रीय असमानता के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :–

सामाजिक असमानता

सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत और नैतिकता ख़त्म होता जा रहा है. व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को जाति और धर्म में बाँटना जायज नहीं है।

आर्थिक असमानता

आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों और अरबपतियों की संख्याँ तो बढ़ रही है परन्तु समाज के गरीब लोग या तो जिस हाल में थे आज भी वही पे खड़े हैं या नहीं तो और गरीब ही होते जा रहे हैं. आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की नींव है. आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते. यदि वास्तव में हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो हमें आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना ही होगा।

शैक्षिक असमानता

शैक्षिक असमानता के कारण ही हम समाज में वंचित वर्गों को अच्छी शिक्षा दे पाने में असफल साबित हो रहे हैं. हम जानते हैं कि शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता. शिक्षा ऐसी हो जो हमें सोचना सिखाये, कर्त्तव्य और अधिकार का बोध कराये, हमें हमारा हक़ दिलाये और हमें समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाये. क्या हम ऐसी शिक्षा समाज के सभी वर्गों को दे पाने में सफल साबित हो रहे हैं ।

भौगोलिक असमानता

भौगोलिक असमानता के कारण ही आज हम देश के सभी भागों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं. भारत को विकसित देशों के श्रेणी में लाने के लिए हमें सुदूरवर्ती गाँवों में विकास के किरणों को पहुँचाना होगा. आखिर हम दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के अनुपात में ही अन्य शहरों और गाँवों का विकास करने में असफल क्यों साबित हो रहे हैं? हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा. यदि हम इन्ही शहरों जैसे और शहर बनाने में कामयाब होते हैं तो न सिर्फ इन शहरों पर से लोगों का दवाब कम करने में कामयाब होंगे बल्कि हमें इस तरह के और कई अन्य शहर भी विकसित करने में सफलता मिलेगी जो क्षेत्रीय असफलता को ख़त्म करने में मील का पत्थर साबित होगा।

औद्योगिक असमानता

औद्योगिक असमानता के कारण ही आज हमें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पर रहा है. ऐसा देखा जा रहा है कि जिस शहर में पहले से ही बहुत सारे उद्योग–धंधे लगे हुए हैं आज भी उन्ही जगहों पर नए–नए उद्योग और कल–कारखाने लगते जा रहे हैं. हमें नए–नए औद्योगिक शहर बसाने की जरुरत है. इसके दो फायदे होंगे. एक तो पुराने औद्योगिक शहरों पर जो लोगों का बोझ बढ़ता जा रहा है वह कम होगा और दूसरा हम नए औद्योगिक शहर बसाने में भी कामयाब होंगे.इसी तरह बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रेल और कृषि आदि अनेक क्षेत्रों में असमानताओं से आम जनों को जूझना पर रहा है. कहीं चौबीसों घंटे बिजली तो कहीं आज भी लोग लालटेन और ढिबरी युग में जीने को विवश हैं. कहीं पानी ही पानी तो कहीं पानी के लिए हाहाकार. कहीं पक्की सड़कों की भरमार तो कहीं कच्ची सड़क भी नहीं. कहीं बड़े–बड़े अस्पताल तो कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं. कहीं रेलवे लाइनों की जाल तो कहीं रेलवे का घोर अभाव.।

लैंगिक असमानता

लैंगिक असमानता भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पित़सत्ताात्मकक व्यमवस्था में निहित है, प्रसिद् समाजशास्त्री सिल्विया वाब्लें के अनुसार पित़सत्ताात्मकक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यकवस्थार है, जिसमें आदमी और पर अपना प्रभुत्वत जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोष्णस करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्क़ तिक घटना है । पित़सत्ताात्मयक व्ययवस्थाा ने अपनी वैधता और स्वीपक़ति हमारे धामिर्कक विश्वादसों चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्योंव न हो से प्राइज़ की है ।

क्षेत्रीय असमानता से निपटने का तरीका

देश के आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों से निपटने के क्रम में एशियाई उदाहरण बहुत काम आ सकते हैं। देश के 11 राज्यों को विशेष दर्जा हासिल है। यह संविधानेतर दर्जा सबसे पहले 1969 में राष्टड्डीय विकास परिषद ने दिया। इस परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल थे। ये 11 राज्य ऊंचे पर्वतों और गहरी घाटियों वाले हैं जहां जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या का अहम हिस्सा जनजातीय है, जो देश के सीमावर्ती इलाके हैं और सामरिक दृष्टिड्ड से महत्त्वपूर्ण हैं, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़े हुए हैं और इनकी अपनी वित्त व्यवस्था बहुत दुरुस्त नहीं है।

बिहर इन मानकों पर खरा नहीं उतरता। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं। यह किस्सा काफी हद तक आरक्षण की याद दिलाता है। आरक्षण की व्यवस्था शुरुआत में केवल 10 साल के लिए की गई थी वह भी सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए। अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वैसी ही है जैसे आरक्षण को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा अन्य जातियों को देने की मांग।

विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को कई तरह की रियायतें और लाभ मिलते हैं। मसलन, उत्पाद शुल्क और आयकर में छूट, 30 फीसदी सामान्य केंद्रीय योजनागत सहायता तथा ऐसी सहायता का 90 फीसदी अनुदान के रूप में। जबकि अन्य राज्यों के लिए यह केवल 30 फीसदी ही रहता है। उस लिहाज से देखा जाए तो

गाडगिल–मुखर्जी फॉर्मूले के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार को सामान्य केंद्रीय योजना सहायता का 11 फीसदी हिस्सा आवंटित किया गया था। ऐसे में यह समझ पाना कठिन है कि आखिर बिना सामान्य केंद्रीय योजनागत सहायता का 30 फीसदी बढ़ाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो कैसे? गत 18 अगस्त को आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की ताकि वहां बुनियादी विकास किया जा सके। बिहार को सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, रिफाइनरी और बिजली संयंत्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं की सख्त आवश्यकता है। साल के अंत तक वहां विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष का कहना है कि इस घोषणा के चुनावी निहितार्थ हैं। राजनीति को परे हटा दें तो भी यह बात भारत में क्षेत्रीय असमानता के प्रश्न के लिए राहत भरी है।

क्षेत्रीय असमानता की बात करें तो भारत एक तरह से मिनी एशिया के समान है लेकिन यहां अंतर पर इतना जोर नहीं है। एशियाई विकास बैंक के मुताबिक वर्ष 2012 में एशिया में सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, ब्रुनेई दारुस्सलाम, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे छोटे देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 21,620 डॉलर से 54,040 डॉलर के बीच थी। यह प्रति व्यक्ति आय निचले स्तर पर मौजूद देशों की तुलना में 20 से 50 गुना तक ज्यादा थी। अफगानिस्तान, नेपाल, कंबोडिया, ताजिकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश इस सूची में सबसे नीचे थे और इनकी प्रति व्यक्ति आय 690 डॉलर से 1,010 डॉलर के बीच थी। अफगानिस्तान जैसे संघर्षग्रस्त देशों का आर्थिक प्रदर्शन तो और भी बुरा था। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर जैसे राज्य अफगानिस्तान जैसे देश नहीं हैं लेकिन इन राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति का असर आर्थिक प्रदर्शन पर भी पड़ता है।

देश के विभिन्न राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों की बात करें तो गोवा, दिल्ली, सिक्किम, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य शीर्ष पर हैं। इन राज्यों में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) फैक्टर कॉस्ट के आधार पर 2014–15 में 1,43,677 रुपये और 2,24,138 रुपये के बीच रहा। यह अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एनडीपी 75,420 रुपये की तुलना में 1.9 फीसदी बेहतर रहा। उसी वर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश मणिपुर, असम और झारखंड इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रहे और उनका प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 31,199 रुपये से 46,131 रुपये के बीच रहा। यह पूरे देश के एनडीपी की तुलना में 61 फीसदी कम था।

निश्चित तौर पर विभिन्न मुल्कों के बीच की असमानता एक देश के अलग–अलग हिस्सों की तुलना में अधिक होती है। एक देश में आमतौर पर आवागमन आसान होता है तो लोग अक्सर गरीब से अमीर इलाकों की ओर सफर करते हैं और इस प्रक्रिया में असमानता को कम करते हैं। इतना ही नहीं। एक महाद्वीप के देश एक दूसरे की नीतियों का अनुकरण कर सकते हैं लेकिन वे एक ही केंद्रीय नीति के तहत काम नहीं कर सकते। तथापि एशिया के विभिन्न देशों में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता से कई सबक सीखे जा सकते हैं।

वर्ष 1973 से एशियाई विकास बैंक एशियाई विकास फंड की मदद से अपेक्षाकृत पिछड़े देशों की मदद पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विकास बैंक के सबसे गरीब सदस्य देशों के बीच विकास संबंधी अंतराल को दूर करना चाहता है। इसके लिए वह अनुदान और ऋण प्रदान करता है। यह ऋण 32 सालों के लिए होता है और आठ साल की अतिरिक्त अवधि होती है। इस पर 1 फीसदी और 1.5 फीसदी ब्याज लगता है। एशिया में यह सहायता पाने वालों और देश में विशेष राज्य का दर्जा पाने वालों की स्थिति कमोबेश एक सी है। प्रथमदृष्टड्डया ऐसा कोई बड़ा प्रमाण नहीं मिलता है कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से वहां विकास की कोई लहर चल पड़ी हो। इसी तरह अपेक्षाकृत गरीब एशियाई देश भी अनुदान के बावजूद एशिया के शेष देशों की तुलना में धीमी गति से विकसित हो रहे हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, थाइलैंड और मलेशिया एशियाई समृद्घि के झंडाबरदार बने हुए हैं। एशियाई विकास फंड से तीन ऐसे सबक निकलते हैं जो भारत की क्षेत्रीय असमानता दूर करने में मदद कर सकते हैं। पहला, कानून व्यवस्था तथा संघर्ष का निदान विकास का पहला पैमाना है। अफगानिस्तान में परियोजना क्रियान्वयन की निम्न दर हताश करने वाली है। विकास संबंधी बेहतर नतीजों के लिए शांति और स्थिरता अहम हैं। जो सरकार सामान्य कामकाज करने तक में विफल हो उससे विकास के मोर्चे पर आगे बढऩे की उम्मीद बेमानी है।

अक्सर क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाले हस्तक्षेप बहुत बढिय़ा प्रतिफल मुहैया कराते हैं। ग्रेटर मेकॉन्ग सबरीजन (जीएमएस) सहयोग कार्यक्रम इसका उदाहरण है। बुनियादी ढांचे की बदौलत बढ़ता संचार और परिवहन कॉरिडोर को आर्थिक कॉरिडोर में बदलना, सीमापार लोगों और वस्तुओं के बेहतर आवागमन के साथ प्रतिस्पर्धा के स्तर में सुधार करना और मूल्य शृंखला का निर्माण गरीब देशों के लिए फायदेमंद होते हैं। लाओस पीडीआर और कंबोडिया इसके बढिय़ा उदाहरण हैं। तीसरा, सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन के पास नीतियों का क्रियान्वयन और परियोजनाओं का स्वामित्व होना चाहिए। बिना किसी सोच विचार के अगर सड़क, विद्यालय या अस्पताल निर्माण पर धन खर्च किया जाए तो वांछित निष्कर्ष शायद ही हासिल हो सकें? जरूरत यह है कि हम अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों या देशों की मदद सही तरीके से करें।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय असमानता, समस्याकएं के कारण ही आज हम देश के सभी भागों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं. भारत को विकसित देशों के श्रेणी में लाने के लिए हमें सुदूरवर्ती गाँवों में विकास के किरणों को पहुँचाना होगा ! उपरोक्त सोध अध्ययन से ये पता चलता है कि क्षेत्रीय असमानता किसी भी देश को विकसित बनाने में सबसे बडी बाधा बनी हुई है, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक,

धामिक, राजनीतिक, भौगोलिक समनाता बनाये रखने के लिये इन विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जाये ताकि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ0 विजय शंकर उपाध्याय :भारत की जनजातीय संस्कृति, आदिवासी लोक कला परिषद, भोपाल, 2004*
2. *डॉ0 विजय चौरसिया : भारत की जनजातीय संस्कृति, आदिवासी लोक कला परिषद, भोपाल, 2004*
3 *डॉ0 वेरियर एल्विनः द बैगा, आक्फोर्ड यूनिवर्सिटी, 1926*
4. *डॉ0 सुरेश मिश्रः इतिहास के पन्नों से, स्वराज संस्थान, संचालनालय संस्कृति भवन, भोपाल, 2005*
5. *डॉ0 श्याम सुन्दर बादल :बुन्देली का फाग साहित्य, आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, 2000*
6. *"आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थव्यवस्था की स्थिति". वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. जुलाई 2014. अभिगमन तिथिः जुलाई 2014.*

पत्र – पत्रिकाएँ

1. *चौमासा : निरंजन महावर कपिल तिवारी, लोक कला परिषद भोपाल,*
2. *सुराज स्वतंत्रता के चालिसवी वर्षगांठ पर : श्री घनश्याम शर्मा एवं कपिल तिवारी, लोक कला परिषद भोपाल,*
3. *वन्या संदर्भ (पाक्षिक) : श्री राम तिवारी एवं उदय केशरी, राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स, भोपाल*
4. *संधान : श्रीमती विराज दुबे, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल*
5. *लोक परम्पराओं के रास्ते विकास की यात्रा : निलेश देशाई, आदर्श प्रिन्टर्स एवं पब्लिर्स सेन्टर भोपाल*
6. *कल्याणिका : बाबा कल्याण दास जी, कल्याणिका सेवा आश्रम अमरकंटक*